Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to undertake caste census in Census 2021-laid.

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया): हमारा देश जातिगत समाज है । अब प्रश्न उठता है कि किन-किन जातियों की संख्या कितनी हैं । प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यह होना भी अनिवार्य है । संख्या बल ही उस जाति के अस्तित्व का निर्धारण करता है । मुख्यतः आरक्षण को ही आधार मान लिया जाय तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग की व्यवस्था हमारे संविधान में दी गई है । यह संविधान की मूल व्यवस्था और भावना भी है । उसी को आधार मान कर हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री, बिहार, विधान सभा एवं अन्य प्लेटफार्म पर यह मांगें उठाते आ रहे हैं कि प्रस्तावित भारत की जनगणना 2021 को जातिगत आधारित जनगणना केन्द्र सरकार अवश्य करा ले । इससे सारी स्थिति साफ हो जायेगी । जातिगत आंकड़ों को लेकर जो भी दुविधा हो रही है वह समाप्त हो जायेगी । कई राज्यों की सरकारें जातिगत जनगणना चाहती है, उनकी भी जातिगत आधारित जनगणना की आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी ।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि 2021 की प्रस्तावित राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत आधारित जनगणना को शामिल किया जाय ।